मुखर होते छात्र असंतोष के स्वर

योगेंद्र यादव

भगत सिंह की जयंती पर कई तरह की बेमतलब की रस्में निभाई जाती हैं : समारोहों का आयोजन किया जाता है, श्रद्धांजलियां दी जाती हैं, उनके चित्रों पर माल्यार्पण किया जाता है, भाषण दिये जाते हैं और क्या कुछ नहीं। एकदम उसी तरह की चीजें जिनका कि खुद यह महान क्रांतिकारी मजाक उड़ाते। इतने वर्षों में शहीद भगत सिंह जोशीले लेकिन बिना किसी देशभक्तिपूर्ण विचारधारा वाले उग्र राष्ट्रवाद का एक खोखला प्रतीक बनकर रह गये हैं।

एक क्रांतिकारी को याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है हमारे वर्तमान और भविष्य के बारे में यह सवाल करना कि युवा किस तरह भारत के भविष्य को नये रूप में गढ़ सकता है?

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में छात्राओं के नेतृत्व में हाल में किया गया अभूतपूर्व विरोध प्रदर्शन एक बार फिर युवा राजनीति की ओर ध्यान आकृष्ट करता है। देश में पिछले दो साल के दौरान कई विश्वविद्यालयों में विरोध प्रदर्शन की घटनाएं हुई हैं- एफटीआईआई पुणे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, कोलकाता की जाधवपुर यूनिवर्सिटी, हैदराबाद की सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी और अब बीएचयू में विरोध प्रदर्शन। क्या इन विरोध प्रदर्शनों का आपस में कोई संबंध है? आज का युवा अल्हड़, करिअर-उन्मुख और जिंदादिल प्राणी है तथा सामाजिक परिवर्तन की बजाय सोशल मीडिया में उसकी ज्यादा रुचि है। समस्या यही है कि हर उम्रदराज पीढ़ी ने अपने से छोटी उम्र वालों को हमेशा इसी नजर से देखा। हर पीढ़ी में बड़ी संख्या में ऐसे लोग होते हैं जो कि पूर्व निर्धारित व्यवस्था के तहत ही सफलता और शोहरत अर्जित करना चाहते हैं। हर पीढ़ी में ऐसा महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक वर्ग होता है जो कि व्यवस्था का विरोध करता है और इसे पुन: परिभाषित करता है। इस पीढ़ी में विचारशील युवाओं की कोई कमी नहीं है और वे अपने व्यक्तिगत करिअर को प्राथमिकता देने की बजाय कुछ बड़ा करना चाहते हैं।

इससे बचने का एक और रास्ता है। ऐसा लगेगा कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में घटनाओं में कोई समानता नहीं है। उनके मुद्दे अलग-अलग हैं। एफटीआईआई के विरोध प्रदर्शन की वजह एक प्रतिष्ठित संस्थान पर एक अक्षम चेयरपर्सन थोपना थी, जबकि हैदराबाद का विरोध प्रदर्शन एक छात्र की वजह से हुआ था। बीएचयू में विरोध प्रदर्शन की वजह लिंग के आधार पर भेदभाव और यौन प्रताड़ना रहे। जहां तक जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी का मामला है, वहां विद्यार्थियों के भड़कने की वजह कुछ कथित 'राष्ट्र विरोधी' घटनाएं रहीं। अन्य जगहों पर विरोध प्रदर्शन स्वाभाविक प्रतिक्रिया थे। इन प्रदर्शनों की राजनीति भी एकदम अलग है। जेएनयू में प्रदर्शनकारी युवा जहां वामपंथी विचारधारा के हैं वहीं हैदराबाद में अंबेडकरवादी। लेकिन हाल के दिनों में जिन अन्य परिसरों में अशांति का माहौल देखा गया, उनके मामले में छात्र प्रदर्शनों पर इस तरह का ठप्पा लगाना मुश्किल होगा।

दरअसल युवाओं के असंतोष की इन घटनाओं में एक समानता है। छात्रों के विरोध प्रदर्शन की ये तमाम घटनाएं मौजूदा शासकों की ओर से उच्च शिक्षण संस्थानों में नयी व्यवस्था थोपने की कोशिशों के विरोध को दर्शाती हैं। यह सरकार उच्च शिक्षा के भगवाकरण से कहीं ज्यादा इसका स्तर गिराने में लगी है। नये पाठ्यक्रम से लोगों के दिमाग घुमाने से कहीं ज्यादा सरकार उच्च शिक्षण संस्थाओं को राजनीतिक रूप से कब्जाने की इच्छुक है। बौद्धिक संसाधनों द्वारा यह सरकार अब अनुशासन को मोहरा बनाने पर उतर आई है।

उच्च शिक्षण संस्थाओं में इस अनुशासन के कई रूप हैं। संदिग्ध बौद्धिक प्रमाण वाले वफादार मैनेजरों को उच्च शिक्षण संस्थाओं का प्रमुख नियुक्त करने की बातें पहले कभी नहीं सुनी थीं, लेकिन अब यह मानक बन गया है। स्वायत्तता की बातें हवा हो गई हैं और फिर इन प्रशासकों का इस्तेमाल यूनिवर्सिटी निकायों तथा संकाय पदों को कब्जाने के लिए किया जाता है। कांग्रेस तथा वामदलों की पिछली सरकारें भी इस तरह के गुनाह करने की दोषी रही हैं लेकिन भाजपा के राज में इसका स्तर बहुत नीचे चला गया है। संघ परिवार क्योंकि देश में कभी भी पहले अथवा दूसरे दर्जे के बुद्धिजीवियों को आकर्षित नहीं कर पाया है, इस वजह से इस तरह की घटनाएं पहले से ही घटिया यूनिवर्सिटी संकाय तथा प्रशासन के स्तर को और गिरा देती हैं। विद्यार्थियों के लिए इस अनुशासन का मतलब अक्सर उन्हें नादान बच्चा मानना ही होता है। इसके साथ-साथ यूनिवर्सिटी द्वारा खुली बहस, बोलने की आजादी तथा जाहिर तौर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दरवाजे बंद कर उनका गैर-राजनीतिकरण कर दिया जाता है। दरअसल, यह सब उच्च शिक्षा के निजीकरण तथा शिक्षा में पहले से ही व्याप्त असमानताओं पर जोर देने के संदर्भ में ही किया जा रहा है।

छात्र इसी बात के खिलाफ विरोध जता रहे हैं। वे उच्च शिक्षा की इस नयी व्यवस्था और इसके अनुशासन के तरीकों का विरोध कर रहे हैं। वे इस उच्च शिक्षा के सत्तावादी तथा अधिकारवादी प्रबंधकों के खिलाफ बगावत पर उतर रहे हैं। वे किसी के द्वारा चुप करा दिये जाने को तैयार नहीं हैं। इस विरोध प्रदर्शन से हासिल क्या होगा? इस बारे में कोई निश्चित निष्कर्ष निकालना अभी जल्दबाजी होगा और हमें बहुत ज्यादा समझदार होने के प्रलोभन से भी बचना चाहिए। लेकिन एक बात एकदम साफ है : सरकार अब तक युवाओं को दबा पाने में नाकाम ही रही है। जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी तथा हैदराबाद यूनिवर्सिटी में इस साल के विद्यार्थी यूनियनों के चुनाव इस बात की पुष्टि करते हैं। अलग-अलग विश्वविद्यालयों में विजेता अलग-अलग संगठनों से संबंधित हैं लेकिन यह बात सच है कि सरकार समर्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को हर जगह हार का सामना करना पड़ा। यह कोई संयोग नहीं है कि अधिकतर विरोध प्रदर्शनों की अगुवाई महिला विद्यार्थियों तथा अल्पसंख्यक सामाजिक समुदायों के छात्रों ने की। लेकिन क्या यह प्रतिरोध देश की भावी राजनीति को आकार दे पायेगा? इस सवाल का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि इस प्रतिरोध की दिशा कैसी रहती है। संगठनात्मक तौर पर इन विरोध प्रदर्शनों में तालमेल क्या संभव हो पायेगा? कैंपस के भीतर होने वाले इन प्रदर्शनों को क्या शिक्षा में असमानता तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध न होने जैसे मुद्दों को लेकर कैंपस के बाहर युवाओं में बढ़ते असंतोष के साथ जोड़ा जा सकेगा? वैचारिक तौर पर क्या इन सब को भारत की नयी सोच के साथ जोड़ा जा सकेगा?

ये बड़े सवाल हैं, उस तरह के सवाल जैसे कि भगत सिंह ने हमें पूछना सिखाये। अगर वह आज जिंदा होते तो वह निश्चित रूप से ये सवाल पूछते और बीएचयू की छात्राओं के विरोध पर गर्व करते।

योगेन्द्र यादव
मार्गदर्शक,
यूथ फॉर स्वराज